मल्टीमीडिया प्रशिक्षण किट

समूह चर्चा और केस अध्ययन: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना की स्वतंत्रता का हैंडआउट

डेविड सौतेर् द्वारा विकसित

समूह चर्चा में इस्तेमाल के लिए प्रश्न

1. मेरे देश में / हमारे देशों में अभिव्यक्ति के अवसरों और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के प्रयोग पर इंटरनेट के आने का क्या प्रभाव पड़ा है ?
2. क्या इंटरनेट पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या इंटरनेट पर सामग्री के उपयोग की कोई सीमा होनी चाहिए? इंटरनेट के परिपेक्ष्य में सरकारों और अधिकारों पेशेवरों को अभिव्यक्ति और अन्य अधिकारों की स्वतंत्रता जो अंतरराष्ट्रीय अधिकार शासन में शामिल किए गए हैं,के बीच संतुलन को कैसे संबोधित करना चाहिए?
3. मेरे देश/ हमारे देशों में इंटरनेट के माध्यम से सूचना की स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए किस प्रकार के अवसर मौजूद हैं?
4. अभिव्यक्ति और सूचना की स्वतंत्रता की स्वतंत्रता के संबंध में इंटरनेट व्यवसायों और बिचौलियों की क्या भूमिका है?

मुसलमानों की निर्दोषिता

नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (ICCPR) का अनुच्छेद 19 राजनीतिक अभिव्यक्ति सहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है. मानवाधिकार परिषद और विचार और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए और अधिकार के संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने स्पष्ट किया है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति में शामिल है दूसरों के द्वारा संभावित रूप से आक्रामक माना जाने वाले विचारों और राय को व्यक्त करने का अधिकार भी उदाहरण के लिए, धार्मिक विश्वास के आधार पर अभिव्यक्त किये जाने वाले विचार भी. जबकि कुछ देशों में ईश्वर निन्दा के अपराध के खिलाफ धार्मिक विश्वासियों की रक्षा का कानून है, ये अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार शासन के जनादेश के दायरे में शामिल नहीं होते हैं. तथापि , नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन निषेध और नस्लीय भेदभाव करने और 'शह' नस्लीय श्रेष्ठता या घृणा के आधार पर विचारों के प्रसार 'के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकारों के द्वारा कार्रवाई की अपेक्षा रखती है.

“मुसलमानों की मासूमियत” संयुक्त राज्य अमेरिका के एक इस्लाम विरोधी कार्यकर्ता द्वारा बनाये गए एक वीडियो का टाइटल है, जिसकी स्पष्ट मंशा है मुसलमानों को नाराज करने और धार्मिक दुश्मनी को बढ़ावा देने की. वीडियो में शामिल सामग्री में से कुछ सामग्री ऐसी है मुस्लिम अनुयायियों द्वारा माना निंदात्मक जा सकता है . यह वीडियो सक्रिय रूप से बहुतायत संख्या में दक्षिण पंथी चरमपंथियों द्वारा और संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और अन्य जगहों में संगठनों द्वारा प्रचारित और प्रसारित किया

गया था जिनका सांप्रदायिक दुश्मनी भड़काने का एक रिकार्ड है. वीडियो से उद्धरण जुलाई 2012 में यूट्यूब पर अपलोड किया गया था और बाद में मिस्र के टेलीविजन पर प्रसारित भी हुआ था. वीडियो के बारे में खबर के व्यापक प्रचार-प्रसार बनिस्बत उसे देखने से, ने बहुत सारे देशों में हिंसात्मक प्रदर्शनों को हवा दी , जिसके परिणामस्वरूप , ऐसा कहा जाता है, 75 लोगो को अपनी जान देनी पडी. इन घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि इंटरनेट अब दुनिया भर में सूचना, अफवाह और अभियान गतिविधि को किस त्वरित गति के साथ विश्व के एक कोने से दुसरे कोने तक फैला सकने में सक्षम है.

कुछ नेताओं और विशेष रूप से मुस्लिम देशों में धार्मिक नेताओं ने, वीडियो पर प्रतिबंध लगाने की मांग की और इस आह्वाहन के लिए ऑनलाइन अभियान साइट change.org के माध्यम से 60,000 से अधिक हस्ताक्षर हासिल किये. कुछ मामलों में, सेंसरशिप के लिए यह मांग धार्मिक अपराध और / या अभद्र भाषा पर आधारित थी; अन्य में, वे सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के विषय में भय पर आधारित थी (और इसलिए ICCPR की अनुच्छेद 19 (3) के तहत जो प्रावधान रखता है अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध "राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के संरक्षण के लिए"). हालांकि, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कुछ कार्यकर्ताओं जवाब दिया कि, अभद्र भाषा के खिलाफ उचित प्रतिक्रिया अभिव्यक्ति को सीमित करने से नहीं लेकिन प्रभावहीन बनाने के लिए वैकल्पिक अभिव्यक्ति को प्रतिपादित करे. उस दृष्टिकोण का विचार और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत द्वारा सामान्य संदर्भ में समर्थन किया गया है. इस वीडियो के

प्रसारण से उठे विवाद ने यह सवाल उठाये कि क्या और किस हद तक तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के परिपेक्ष्य में द्वेषपूर्ण भाषण को मानक के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, यानि इसकी सीमाएं कहा पर निर्धारित होनी चाहिए.

गूगल जो यूट्यूब का मालिक है, ने फैसला किया है कि यह वीडियो अभद्र भाषा के बारे में सेवा की उसकी शर्तों का उल्लंघन नहीं करता है , क्योंकि गूगल के विचार में, यह हमला एक धर्म पर किया गया है अनुयायियों, पर नहीं. हालांकि, यह अस्थायी रूप से कुछ देशों में यूट्यूब पर वीडियो के लिए उपयोग अवरुद्ध कर दिया गया था क्योंकि इस बात का अंदेशा था की इससे हिंसा को बढ़ावा मिल सकता है. निम्नानुसार गूगल ने टिप्पणी की: हम ... मानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के निर्बाध परिचालन की कुछ सीमाएं है और ... वे होनी चाहिए. कठिनाई है उन सीमाओं को तय करने की. गूगल जैसी एक कंपनी के लिए जो 100 से अधिक देशों में सेवा प्रदान करती है- सभी विभिन्न राष्ट्रीय कानूनों और सांस्कृतिक मानदंडों के साथ- के लिए एक चुनौती है जो यह हम हर दिन कई बार सामना करते हैं ." कुछ सरकारों ने सामान्य रूप में पूरे यूट्यूब वेबसाइट और / या गूगल सेवाओं को अपने नागरिकों के लिए उपयोग अवरुद्ध कर दिया क्योंकि उनके लिए यह वीडियो बिना किसी अवरोध के देखने के लिए सामान्य रूप से सहजता से उपलब्ध था.

इस उदाहरण के बारे में सूचना और टिप्पणी प्राप्त की जा सकती है:

- en.wikipedia.org/wiki/Innocence_of_Muslims
- www.guardian.co.uk/film/filmblog/2012/sep/17/innocence-of-muslims-demonstration-film
- www.article19.org/data/files/pdfs/publications/blasphemy-hate-speech-article.pdf

- www.nytimes.com/2012/09/15/world/middleeast/google-wont-rethink-anti-islam-videos-status.html?_r=0
- www.foreignpolicy.com/articles/2012/10/05/the_innocence_of_youtube

चर्चा के लिए प्रश्न

1. अधिकार कार्यकर्ताओं को कैसे ऑनलाइन अभद्र भाषा के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए?
2. क्या सरकारों और इंटरनेट व्यवसायों को सक्षम करने और अभिव्यक्ति की ऑनलाइन स्वतंत्रता की रक्षा करने में सार्वजनिक व्यवस्था पर अभिव्यक्ति के प्रभाव पर विचार करना चाहिए?
3. क्या ऑनलाइन सेवा प्रदाताओं द्वारा उनकी साइटों पर होस्ट होने वाली सामग्री को राष्ट्रीय मानदंडों और धार्मिक विश्वासों के मद्देनजर आकलन करके रखा जाना चाहिए?
4. कैसे इस तरह की घटनाओं के उदाहरण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मद्देनजर विभिन्न देशों में जनता की राय को प्रभावित करते हैं?

समूह चर्चा के लिए **केस अध्ययन** और उदाहरण - परिदृश्य 2

मिस्र में इंटरनेट को अवरुद्ध करना और फिल्टरिंग

ऐसा माना जाता है कि 2011 में मिस्र में मुबारक के शासन को उखाड़ फेंकने की घटनाओं में सामाजिक नेटवर्किंग और,विशेष रूप से इंटरनेट ने व्यापक रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उस वर्ष के अंत तक, मिस्र में फेसबुक उपयोगकर्ताओं की संख्या दुनिया भर में, जनसंख्या के संबंध में उच्चतम हो गयी थी.

मिस्र में क्रांति से पहले के वर्षों में इंटरनेट की उपयोगिता तेजी से बढ़ी और मुबारक सरकार द्वारा इसको राष्ट्रीय आर्थिक विकास के एक साधन के रूप में पदोन्नत किया गया. हालांकि, सरकार ने भी इंटरनेट पर सामग्री के अभिव्यक्ति और उपयोग पर नजर रखी. तीन मुद्दों को मानवाधिकार संगठनों द्वारा चिंताओं के रूप में उठाया गया:

- उदाहरण के लिए सार्वजनिक नैतिकता के आधार पर, फिल्टरिंग और कुछ सामग्री के अवरुद्ध, के आरोप
- इंटरनेट कैफे उपयोगकर्ताओं 'पहचान के अनिवार्य रिकॉर्डिंग
- देश के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की आलोचना करने के लिए जिम्मेदार ब्लॉगर्स की गिरफ्तारी और नजरबंदी

मिस्र की क्रांति के दौरान इंटरनेट पर सरकार के हस्तक्षेप की पराकाष्ठा जनवरी 2011 में देखने में आयी. सबसे पहले, अधिकारियों ने ट्विटर और फेसबुक के लिए उपयोग को अवरुद्ध कर दिया जिसका शासन के विरोधियों द्वारा बड़े पैमाने पर विचारों के आदान प्रदान और प्रदर्शनों का आयोजन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था. फिर, अधिकारियों ने पूरी तरह से देश की इंटरनेट कनेक्टिविटी को शट

डाउन और मोबाइल इंटरनेट सहित मोबाइल फोन सेवा, कटौती करने के लिए मोबाइल फोन कंपनियों का आदेश दिया. हालाँकि यह केवल कुछ ही दिनों तक चला, इस कार्रवाई और इसे करने के बाद की अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया ने रेखांकित किया सरकारों और उनके विरोधियों दोनों के लिए इंटरनेट की महत्ता जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति और जानकारी के लिए उपयोग के लिए एक माध्यम के रूप में सशक्त रूप से प्रतिस्थापित हुई.

ऑनलाइन सामग्री से संबंधित मुद्दों पर अभी भी मिस्र में बहस जारी है. यह विशेष रूप से इतनी नैतिक रूप से आक्रामक सामग्री के परिपेक्ष्य में जारी है. मिस्र में क्रांति धार्मिक परंपरावादियों और उदार धर्मनिरपेक्षता दोनों द्वारा समर्थित था. दोनों आम तौर पर राजनीतिक सेंसरशिप का विरोध करते हैं, नैतिक सेंसरशिप पर दोनों के अलग-अलग विचार हैं. 2012 में, देश के अभियोजक जनरल ने एक अदालत के फैसले द्वारा अश्लील वेबसाइटों पर प्रतिबंध लागू करने के लिए सरकारी एजेंसियों को निर्देश देते हुए कहा कि “अभिव्यक्ति और जनता के अधिकार की स्वतंत्रता से ज्यादा प्राथमिकता धर्म, नैतिकता और देशभक्ति की बुनियादी बातों को दी जानी चाहिए. "

इस उदाहरण के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है:

- en.wikipedia.org/wiki/Internet_in_Egypt
- www.freedomhouse.org/sites/default/files/resources/FOTN%202012%20-%20Full%20Report.pdf, pages 164-176
- www.eff.org/deeplinks/2012/11/egyptian-prosecutor-orders-ban-internet-porn
- dailycaller.com/2012/11/08/egypt-moves-to-ban-online-porn-blocking-some-of-the-countrys-most-popular-websites

चर्चा के लिए प्रश्न

1. इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और मानवाधिकार संगठनों को सरकार के इंटरनेट को बंद करने और इंटरनेट सामग्री को ब्लॉक या फिल्टर करने के प्रयासों का जवाब कैसे देना चाहिए?
2. क्या राजनीतिक या यौन प्रकृति की सामग्री और राजनीतिक और यौन सामग्री की सेंसरशिप में कोई विरोधाभास है?
3. क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सरोकार की एक छोटी संख्या के सामाजिक नेटवर्किंग प्रदाताओं के प्रभुत्व से उत्पन्न होती हैं?

समूह चर्चा के लिए केस अध्ययन और उदाहरण - परिदृश्य 3

केन्या में ओपन डाटा

सूचना की स्वतंत्रता, सीधे शब्दों में, सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा नागरिकों के लिए वैध जानकारी कराने की प्रक्रिया तक सीमित नही है. यह पहुँच सक्षम करने के लिए और विभिन्न प्लेटफार्मों, इंटरनेट सहित, पर जानकारी के लिए उपयोग को संभव बनाने के क्रम में कानून बनाने की सरकारों की आवश्यकता है. यह माना जाता है कि इससे सरकार को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में मदद मिलती है. सूचना की स्वतंत्रता उपयोगकर्ताओं और तीसरे पक्षों को सक्षम बनाता है जानकारी एकत्र करने के लिए और ऑनलाइन अपने स्वयं के विश्लेषण प्रकाशित करने के लिए भी. डेटा सेट के रूप में, सूचना कानून की स्वतंत्रता आमतौर पर, नागरिकों को सक्षम बनाता है सरकार की सूचना की जानकारी के एक व्यापक रेंज का उपयोग करने के लिए, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं सहित उन्हें सार्वजनिक बहस के लिए और अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए. इस के

साथ शामिल हो सकता है परामर्श और ऐसी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अन्य उपाय.

केन्या की सरकार का दावा है कि उसने ओपन डाटा पहल से उप-सहारा अफ्रीका में स्वतंत्रता की जानकारी सम्बंधित पहला सूचना पोर्टल अपने नागरिकों के लिए प्रदान किया है. पोर्टल के लक्ष्य को निम्न रूप में वर्णित किया गया था: शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं, आईसीटी डेवलपर्स और आम जनता के लिए एक उपयोगी डिजिटल प्रारूप में सरकार विकास, जनसांख्यिकीय, सांख्यिकीय और व्यय डेटा उपलब्ध करवाया जाये". यह विश्व बैंक की सहायता से 2011 में शुरू किया गया था जो शुरू में राष्ट्रीय जनगणना और सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक सेवाओं पर डेटा को ऑनलाइन पहुँच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था. (पोर्टल होम पेज पर उदाहरण देखा जा सकता है opendata.go.ke). हालांकि 2012 के मध्य तक, 400 से अधिक डेटा सेट, उपलब्ध कराया गया है, उपलब्ध जानकारी में सरकार के अंदर आंतरिक नीति में विचार विमर्श से सम्बद्ध सामग्री को शामिल नहीं किया किया गया था.

कुछ सरकारी विभागों जानकारी के ऑनलाइन प्रकाशन का विरोध कर रहे हैं इस आशय की चिंता को हाल ही में व्यक्त किया गया है. मंत्रालय में पोर्टल के लिए जिम्मेदार स्थायी सचिव ने कहा है कि: हमें संगठनों से डेटा नहीं प्राप्त हो पा रहा है क्योंकि वे दावा करते है कि उस डाटा का स्वामित्व उनके पास है, यहां तक कि उन करदाताओं के पैसे का उपयोग कर के जो डेटा एकत्र किया गया है वो भी. इसने ऑनलाइन स्वतंत्रता सक्षम करने में सरकार के लोकाचार के महत्व के बारे में सवाल उठाया है, और पत्रकारों और अन्य पेशेवरों की भूमिका के बारे में भी जो जनता के लिए जानकारी की व्याख्या के मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकते हैं.

इस उदाहरण के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है:

- opendata.go.ke
- www.princeton.edu/successfulsocieties/content/data/policy_note/PN_id206/Policy_Note_I D206.pdf
- www.nation.co.ke/business/news/Open-data-initiative-has-hit-a-dead-end/-/1006/1617026/-/n18uhrz/-/index.html
- allafrica.com/stories/201212281054.html

चर्चा के लिए प्रश्न

1. सूचना की स्वतंत्रता के लिए सीमाएं किस प्रकार पारिभाषित की जानी चाहिए ताकि इस तरह की गोपनीयता और सुरक्षा के रूप में अन्य अधिकारों की रक्षा की जा सके.
2. क्या वैचारिक स्वतंत्रता वाली सरकार के लिए मुक्त डेटापर्याप्त है, या ऑनलाइन का सार्वजनिक जानकारी के लिए उपयोग एक बहुत व्यापक रेंज के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए?
3. मानवाधिकार संगठनों को सूचना की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए और वे अपने काम में सबसे अधिक प्रभावी ढंग से इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं?

अंतिम सत्र में चर्चा के लिए प्रश्न

1. इंटरनेट पर अभिव्यक्ति और सूचना की स्वतंत्रता को सक्रिय करने, बढ़ावा देने और रक्षा करने में, सरकारों की क्या भूमिका होनी चाहिए?
2. मानवाधिकार संगठनों को इंटरनेट पर अभिव्यक्ति और सूचना की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? वे कैसे अधिकारों की निगरानी और इनके उल्लंघन का जवाब किस तरह देना चाहिए?